

भारत अमेरिका का संबंध

डॉ दीप कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर रक्षा अध्ययन विभाग एस एम कॉलेज चंदौसी

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: —

भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में समान रहा है। दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की (अमेरिका वर्ष 1776 और भारत वर्ष 1947) तथा स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में दोनों ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक रहा है , जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के संदर्भ समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्त्व दिया। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहाँ अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया , वहीं भारत ने गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा का समर्थन किया ।

वर्तमान दौर:—

भारत और अमरीका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिनमें काफी समानताएं हैं। भारत और अमरीका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार सैन्य सहयोग भी बढ़ा है । बहरहाल , अमरीका भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिर ता की वकालत करता रहा है , जिसमें कश्मीर मुद्दे पर तनाव कम करना और परमाणु हथियारों के प्रसार व परीक्षण का परित्याग भी शामिल है। यह अब अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि दोनों देशों के पास एक -दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। यू. एस. कांग्रेसनल सर्विस ने एक पेपर प्रस्तुत किया है , जिसमें भारत-अमेरिकी संबंधों का बहुत ही अच्छा नवीनतम विश्लेषण दिया गया है।

भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से साल 2020 मील का पत्थर साबित हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस साल भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने श्व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया। इसी साल दोनों देशों ने कोविड - 19 महामारी और यहाँ हुए राष्ट्रपति चुनाव के चलते पैदा घरेलू राजनीतिक गतिरोध के बावजूद अपने संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाई और गति प्रदान की । साल 2020 में भारत और अमेरिका के बीच संबंध हर तरह से खूब मजबूत हुए है ।

भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण शबेकार समझौता हुआ जिससे दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की तरफ कदम बढ़ाए । अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा , श्वैश्विक महामारी के बीच संबंध शक्ति का एक स्रोत रहा है । टीका तैयार करने से लेकर हिंद -प्रशांत की सुरक्षा तक दोनों देशों ने 2020 में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और प्रगाढ़ बनाने के लिए मिलकर काम किया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका -भारत व्यापार परिषद और अमेरिका - भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम के जरिए अमेरिका के व्यापार जगत को संबोधित किया । दोनों देशों ने सामरिक ऊर्जा साझेदारी और भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की बैठकें भी हुई , जिनका मकसद द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना था ।

फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 खरीद पर सहमति बनी है। हालिया समझौते के अनुसार , भारत अमेरिका से 24 एम.

इसके साथ ही इस समझौते के तहत अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली , हथियार युक्त एवं गैर हथियार वाले ड्रोन विमानों का आयात किया जाएगा।

भारत-अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण समझौते:

1. सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security of Military Information Agreement) - वर्ष 2002
2. भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (वर्ष 2008)
3. लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics EÚchange Memorandum of Agreement) - वर्ष 2016
5. भारत-अमेरिका सामरिक उर्जा भागीदारी (वर्ष 2017 में घोषित)
6. संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement & COMCAS |) - वर्ष 2018
7. आतंकवाद विरोध पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदल की बैठक (पिछली बैठक मार्च 2019)
8. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता

भारत और अमेरिका के बीच हुए इन समझौतों से एक बड़ा फायदा ये है कि दोनों देशों के संबंध अब एक नई दिशा में बढ़ चले हैं. और ये शायद किसी नई मंजिल तक भी पहुंच जाएं. हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य गठबंधन भी हो जाए . लेकिन, अभी वो मंजिल बहुत दूर है. जैसा कि पाकिस्तान के उदाहरण से स्पष्ट है कि, जो देश औपचारिक रूप से भी अमेरिका के सहयोगी हैं , उन्हें भी मुसीबत के वक्त अमेरिका से मदद मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन , कोई इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि भले ही भारत और अमेरिका के बीच औपचारिक रूप से सैन्य गठबंधन न बने , मगर दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग को काफी बढ़ा सकते हैं ।

अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के लाभ:

आर्थिक क्षेत्र:

अमेरिकी राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा भारत के आर्थिक क्षेत्र के लिये एक बड़ी सफलता है। ध्यातव्य है कि अमेरिका विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष (Trade Surplu) रहता है ।

वर्ष 2018 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 142 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा , जो वर्ष 2017 के द्विपक्षीय व्यापार से 12.6: अधिक है। गौरतलब है कि अमेरिका भारतीय सेवा क्षेत्र और अन्य कई उत्पादों के लिये विश्व का सबसे बड़ा बाजार है।

वर्ष 2018 में भारत से अमेरिका को हुए निर्यात की कीमत लगभग 54.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2017 से 11.9: अधिक) थी और वर्ष 2018 में ही अमेरिका से लगभग 33.5 बिलियन डॉलर (वर्ष 2017 से 30.6: अधिक) की वस्तुओं का आयात किया गया ।

ऐसे में इस यात्रा के दौरान हुए समझौते दोनों देशों की सरकारों के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में एक सकारात्मक और स्थिर भविष्य का संकेत देते हैं ।

रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में:

अमेरिका से 30 नए हेलिकॉप्टरों के आयात के साथ ही इनके कुछ उपकरणों को भारत में ही बनाए जाने की योजना है।

ध्यातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा उपकरणों के व्यापार में तकनीकी के हस्तांतरण को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं ।

इसके साथ ही वर्तमान रक्षा सौदों में सरकारों के साथ-साथ दोनों देशों की रक्षा क्षेत्र से संबंधित निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। जो इस क्षेत्र में उभरती भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिये सकारात्मक संकेत है। (उदाहरण के लिये 2-21 लड़ाकू विमान बनाने के लिये टाटा और लॉकहीड मार्टिन की साझेदारी)

ऊर्जा क्षेत्र:

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिये बड़े पैमाने पर अन्य देशों से होने वाले तेल और गैस आयात पर निर्भर रहता है। वर्ष 2017 में भारत ने अमेरिका से 9.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया वहीं वर्ष 2018 में यह आयात बढ़कर 48.2 मिलियन बैरल हो गया है।

अमेरिका से तेल और गैस के आयात को बढ़ाने से ऊर्जा जरूरतों के लिये किसी एक देश पर भारत की निर्भरता में कमी आएगी, जिससे विषम परिस्थितियों में ऊर्जा की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।

इस यात्रा के दौरान प्रशासन, रक्षा और व्यापार के अतिरिक्त दोनों देशों ने नागरिकों के बीच (People & People) संबंधों को बढ़ाने में 'यंग इनोवेटर्स इंटरनशिप' परियोजना, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में - GDP जैसे प्रयासों को रेखांकित किया गया है। इन योजनाओं से भारतीय युवाओं में क्षमता विकास के साथ ही दोनों देशों के नागरिक संबंधों को मजबूत करने में सहायता प्राप्त होगी।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र :

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में अमेरिका ने चीन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के बजाय क्षेत्र में सभी हितधारकों को साथ लाने की भारतीय नीति का समर्थन किया। जो इस क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण से एक बड़ी सफलता है।

अमेरिका से उन्नत तकनीकी के नौसैनिक हेलिकॉप्टरों के आयात और भारत-अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यासों से भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group & NSG) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर अमेरिका का समर्थन दक्षिण एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्त्व को दर्शाता है। इसके साथ ही ब्लू डॉट नेटवर्क जैसे प्रयासों से भारत को इस क्षेत्र में चीन के दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए भारत को नवीन तकनीकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका सहित अन्य देशों से भी व्यापक विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

भारत द्वारा सेवा क्षेत्र की ही तरह विभिन्न क्षेत्रों (रक्षा, सूक्ष्म तकनीकी) में स्वदेशी तकनीकी और क्षमता के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

भारत-अमेरिका संबंधों के सुधार और दोनों देशों अनेक क्षेत्रों (जैसे - तकनीकी, अर्थव्यवस्था आदि) के विकास में प्रवासी भारतीयों (वर्तमान आबादी लगभग 4 मिलियन) की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है, ऐसे में इस क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग (जैसे- वीजा नियमों में सुधार आदि) के प्रयास किये जाने चाहिये।

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों के माध्यम से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई (उदाहरण - प्रतिबंध) का प्रयास करना चाहिये।

विश्व के अन्य क्षेत्रों (जैसे - अफ्रीकी देशों) आदि में नए अवसरों की तलाश और चुनौतियों के निवारण में जैसे प्रयासों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिये।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये बहुपक्षीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

पावर पॉलिटिक्स:

विश्व व्यवस्था के मुद्दों और लोकतांत्रिक आदर्शों से परे , भारत को चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका की जरूरत है खासकर इसलिए क्योंकि हम सशस्त्र बलों और रक्षा औद्योगिक आधार को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक पुनर्गठन और सुधार को पूरा करने में विफल रहे हैं. लेकिन उसी कारण से, अमेरिका को भी चीन की बढ़ती ताकत को दूर करने के लिए भारत की जरूरत है ।

इसलिए, भारत- अमेरिका संबंधों के पीछे एक शॉर्ट-टर्म लॉजिक है. लेकिन लंबी अवधि में, वो समझौते भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं . क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक , आर्थिक रूप से जीवंत और तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता पाने की कोशिश कर रहे हैं । एक वैश्विक शक्ति जिसकी नियति के साथ -साथ उसकी निर्णय स्वायत्तता अपने हाथों में है अमेरिका ने एक बार कहा था कि वह भारत को इसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करने के लिए तैयार है लेकिन आज , उनकी अपनी विदेश नीति का संकुचित दृष्टिकोण इस वादे को कमजोर कर रहा है ।

संयुक्त राज्य में भारत के सॉफ्ट पॉवर पर प्रवासियों का प्रभाव

भारत की सॉफ्ट पॉवर का जरिया इसके प्रवासी हैं, जो इसकी संपत्ति हैं । भारतीय प्रवासियों का अमेरिका में ।

तीन चरणों में विकास हुआ है, पहला शिक्षा और रोजगार की तलाश , दूसरा, प्रेषण का प्रमुख स्रोत (2017 में यू.एस से भारत में +10.657 बिलियन का वार्षिक प्रेषण) और तीसरा यू. एस की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले प्रभावी खिलाड़ियों के रूप में 8 अमेरिका के भीतर, भारतीय प्रवासी एक प्रभावी सार्वजनिक कूटनीति उपकरण हैं और अपने नैतिकता , अनुशासन, हस्तक्षेप ना करने और स्थानीय लोगों के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए माने जाते हैं । ये मूल्य अंततः यू.एस में भारतीयों की पहचान बनाने, छवि प्रक्षेपण और छवि बनाने में योगदान करते हैं ।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में :-

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंध विकसित हुए हैं। उन्होंने आशा जताई कि लोकसभा चुनाव के बाद भी संबंधों में और सुधार होने की उम्मीद है । मोदी सरकार के पांच साल और हाल ही में भारत के विदेश सचिव विजय गोखले की अमेरिका की यात्रा पर किए गए एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा कि, जबसे मोदी ने सत्ता संभाली है तब से भारत-अमेरिका का संबंध वास्तव में फला-फूला है ।

विशेष रूप से मैं यह कहूंगा कि जून 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा से हमारे रिश्तों में बहुत प्रगति हुई थी। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि विदेश सचिव गोखले द्वारा किया गया दौरा सिर्फ संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रयास हैं ।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस चुनाव में चाहें जो कोई भी चुना जाए हम उनके साथ भारत-अमेरिका के संबंधों को नया आयाम देंगे। इसमें भारत-अमेरिका के रणनीतिक हित भी शामिल हैं।

भारत का एक मित्र

शुरुआत में ही मैं स्वीकार करता हूं कि अमेरिकी राजदूत नामित होने के बहुत फायदे हैं। विशेषकर , जीवन के सभी पहलुओं के साथ-साथ जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिला , मेरे बारे में आश्चर्यजनक बातें बताने के लिए सामने आए हैं। हालांकि यह सभी सच नहीं भी हो सकता है , लेकिन निश्चय रूप से अच्छा लगता है !

जब मैंने अपना परिचय -पत्र प्रस्तुत किया तब भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशंसा जो मेरे साथ गूंजती रहती है: उन्होंने मुझे " भारत के मित्र" कहा। यह एक ऐसी टिप्पणी है, जिसे अन्य ने भी किया है, उसे मैं बड़ा सम्मान मानता हूँ। "भारत के मित्र" का क्या अर्थ है और मैं यह क्यों सोचता हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, इसे पर मैंने विचार किया है।

जब मैंने सबसे पहले नीति संबंधी मामलों पर अंडर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के रूप में भारत के साथ कार्य करना शुरू किया, हमारे दोनों देशों ने संवेदनशील अमेरिकी तकनीक का सैनिक और पारंपरिक अनुप्रयोगों दोनों के साथ हस्तांतरण संबंधी चुनौतीपूर्ण और कठिन मामलों का सामना किया, जो तथाकथित " दोहरे उपयोग के आइटम्स" हैं। भारत ने इस तकनीक तक पहुंच बढ़ाने की मांग की, जबकि अमेरिका सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी भी हस्तांतरण का उपयोग केवल सहमति के प्रयोजनों के लिए नामित प्राप्तकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक निर्यात नियंत्रण की एक अत्याधुनिक प्रणाली की आवश्यकता होती है जो स्पष्ट रूप से उस समय भारत के पास नहीं थी।

मेरे विचार से जिस तरह से अमेरिका और भारतीय अधिकारियों ने इस हस्तांतरण के लिए संपर्क किया उसने कुछ को मुझे "भारत का एक मित्र" कहने के लिए प्रेरित किया। मैं इस दृष्टिकोण को संक्षेप में बताता हूँ।

इसकी शुरुआत सदैव की भांति सम्मान के साथ हुई है। हालांकि अमेरिका और भारतीय राजनयिक निश्चित रूप से अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य शुरू करते हैं, हमने भी एक-दूसरे को ध्यान से सुना, एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया, और समानताओं तथा परस्पर लाभकारी समाधानों की तलाश की है।

हमने एक-दूसरे पर भरोसा किया है। इसमें खुलापन और स्पष्टता है। " आप जैसा कहते हैं वैसा करो और जैसा करते हो वैसा कहो " यह पुरानी कहावत हो सकती है, लेकिन भरोसा पैदा करना महत्वपूर्ण है।

निश्चित रूप से, हम समय-समय पर असहमत हुए हैं। लेकिन मित्र के रूप में हम अभी भी एक-दूसरे को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से मूलभूत हित समान हैं। इस स्वीकृति ने हमें असहमति के मध्य कार्य करने में समर्थ बनाया है और द्वेष व विद्रोह के बिना तथा निश्चित रूप से अपने रिश्ते को खतरे में डाले बिना अग्रसर हुए हैं।

हमारे दृष्टिकोण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी आत्मविश्वास। क्योंकि मित्र एक-दूसरे के अच्छे इरादों में विश्वास करते हैं, हमने कभी-कभी खतरा उठाते समय आत्मविश्वास का अनुभव किया - यहां तक कि बड़े खतरे में भी, जिसने हमें अंततः वांछित लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता की।

हमारे मूल्य और हित

विविधता, गतिशीलता, बहुधार्मिकता, और बहुलतापूर्ण लोकतंत्रों के सदस्य के रूप में भारतीयों और अमेरिकियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूलभूत मूल्यों का साझा करते हैं, कठिन परिश्रम और उद्यम, मुक्त समाज, मानवाधिकार, और कानून का शासन। केवल फायदे के बजाय, यह मूल्य दृढ़ विश्वास की मित्रता का आधार हैं। हमारे मूल्यों के आधार पर नियमानुसार कार्य करने, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का लाभ उठाने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से करने में हमारे हित समान हैं।

अमेरिका - भारत रणनीतिक भागीदारी

अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी की रूपरेखा दोनों देशों को मजबूत करने तथा इस क्षेत्र पर लाभकारी प्रभाव के लिए बनाई गई है। अभी जो सिद्धांत गिनाए गए हैं वह इसमें सम्मिलित हैं तथा इन्हें अपनाने वाले किसी राष्ट्र के साथ कार्य करने का स्वागत है।

गत 17 वर्षों में अमेरिका और भारत ने मिलकर बहुत प्रगति की है। इसमें हमारा रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास, उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह का कार्य रणनीतिक भागीदारी में अगला कदम, ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता, अमेरिका-भारत व्यापार में लगभग छह - गुणा वृद्धि, रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार योजना तथा भारत को बड़े रक्षा भागीदार के रूप में नामित करना, और वाणिज्य संबंधी बहुत सी अन्य योजनाएं, ऊर्जा, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि सरकार के कई बदलावों में हमारे प्रत्येक देश के बड़े पक्षों की ओर से मजबूत, दृढ़ और निरंतर सहयोग रहा है।

रक्षा और आतंकवाद से मुकाबला

पहला मुख्य स्तंभ है हिंद-प्रशांत क्षेत्र की दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए रक्षा पर हमारा सहयोग तथा आतंकवाद से मुकाबला। इसका एक संबद्ध और समान रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा के तंत्र प्रदाता, शांति के खतरे, विशेष रूप से भारतीय समुद्र और इसके आसपास के खतरे से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग जारी रखना है। हम इस उद्देश्य को कई तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हम गर्मियों नई 22 मंत्रिस्तरीय बातचीत की अपेक्षा करते हैं और दोनों तरफ से कार्यवाही के लिए रोडमैप शामिल करने की आशा है।

सहयोग बढ़ाने का एक तरीका है सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका पहले ही द्विपक्षीय अभ्यासों की विशाल श्रृंखला संचालित कर रहे हैं। हालांकि यह वास्तव में सिंगल - सर्विस रही हैं, यह समय शायद मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित बहु - सेवा अभ्यास पर विचार करने का है। सैन्य अभ्यासों का मामूली विस्तार दोनों देशों को एक-दूसरे से सीखने और एक साथ कार्य करने में सुविधा, सरलता और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

अब मैं रणनीतिक भागीदारी बनाने के दूसरे स्तंभ - आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध पर आते हैं। भारत आर्थिक विकास के मध्य में है जैसेकि वैश्विक अर्थ व्यवस्था में पूरी तरह एकीकृत हो रहा है। परिणामस्वरूप भारत के साथ अमेरिकी व्यापार और निवेश संबंध विकसित हो रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार 2001 में 20 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2016 में 115 बिलियन डॉलर हो गया है। बेशक हमारे बाजारों का जो आकार दिया गया है उनमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में होने काफी गुंजाइश है, और व्यापार को अधिक पारस्परिक बनने की प्रक्रिया में है।

निष्पक्ष और संतुलित व्यापार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के लिए अपने सभी भागीदारों के साथ कार्य करना महत्वपूर्ण है। हम लगातार व्यापार घाटे के प्रति चिंतित हैं, जिसमें भारत के साथ व्यापार शामिल है।

हम सुधार एजेंडा, बाजार पहुंच और बौद्धिक संपदा संरक्षण को और बढ़ावा देना जारी रखने के लिए भारत के कदमों का स्वागत करते हैं। हम भारत के साथ व्यापार और निवेश विवादों को तेजी से हल करने के लिए कार्य करना चाहते हैं। हमारे दृष्टिकोण में पूरी तरह मुक्त और निष्पक्ष व्यापार, भारत के अनवरत दीर्घकालिक विकास दर में सुधार करने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को बढ़ाने में सहयोग करेगा। इस संबंध में वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत को और ऊपर ले जाने की प्रधानमंत्री की दृढ़ता प्रेरणादायक है।

"अमेरिका फर्स्ट" और "मेक इन इंडिया" में विरोधाभास नहीं है। बल्कि एक-दूसरे के बाजारों में निवेश करना पारस्परिक रूप से फायदेमंद होगा यह हमारे आर्थिक आदान -प्रदान और व्यापार की मात्रा में वृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग का मार्गदर्शन और दोनों देशों में रोजगार पैदा करेगा।

लेकिन मुझे आगे बढ़ने दें तथा सुझाव दें कि हमारे आर्थिक संबंध के बारे में रणनीतिक चश्मा लगाने का समय है, ठीक वैसे जैसे हमने रक्षा संबंध के लिए किया है। कई अमेरिकी कंपनियों ने चीनी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए बढ़ती कठिनाइयों की सूचना दी है। इसी तरह से वहां कुछ कंपनियां अपने संचालन को कम कर रही हैं, जबकि अन्य कंपनियां वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रही हैं।

हमारे आर्थिक संबंधों में जोरदार बढ़ोत्तरी निश्चित रूप से व्यापक और गहरी दीर्घ कालिक अमेरिकी प्रतिबद्धता के साथ अमेरिका-भारत रिश्ते में अधिक स्थायित्व प्रदान करेगी। यह हमारे बढ़ते रक्षा और आतंकवादरोधी भागीदारी का पूरक होगा, और इसके मार्ग में पैदा होने वाली किसी भी पॉलिसी मतभेदों को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी के लिए बहुत महत्वाकांक्षी एजेंडा है। आज की अशांत दुनिया में, एक दृढ़ता है और साझेदारी की दृढ़ता हमेशा रहनी चाहिए। मैं सच्चाई से विश्वास करता हूँ कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी रिश्ते की तरह महत्वपूर्ण है - जो अवसर हमारे पास हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उसके परे होने वाले संभावित प्रभाव दोनों ही रूप में। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को पोषित कर रहे हैं। हमारी भागीदारी का असली मूल्य यह है कि हमारे लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए वैश्विक मामलों को सकारात्मक रूप से प्रभावित और सबसे बड़ी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकने में सक्षम बना सकती है। निश्चित रूप से यह होगा, हमें मित्र के रूप में सम्मान, विश्वास, स्वीकृति, भरोसा, लचीलापन और स्थिरता के साथ अपने कार्य करने चाहिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को "सच्चा दोस्त" कहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री वाजपेयी का कथन दोहराया है जिसमें उन्होंने हमारे देशों को "स्वाभाविक मित्र" रूप में वर्णित किया है। अब यह हम पर निर्भर है कि आगे इस शब्दावली को यथार्थ रूप प्रदान करें। हमें एक मजबूत और टिकाऊ होने के साथ लचीली और अनुकूल भागीदारी का निर्माण करना चाहिए। आइए अपने सामने अवसरों को ग्रहण करें, ताकि भावी पीढ़ियां इस समय को अमेरिका-भारत संबंधों के वास्तविक रूपांतरण के रूप में देखें।

संदर्भ सूची :-

- 1- indiatimes.com
2. दृष्टि द विजन
3. यू.एस में भारतीय प्रवासी महत्वपूर्ण क्यों हैं, द इकनोमिक टाइम्स, 2018
4. भारतीय प्रवासी जनजातीय और प्रवासी पहचान, सी. ए. आर.आई.एम भारत, 2013
- 5- inusembassy.gov